केंद्रीय विद्यालय संगठन

बनाम

दामोदर प्रसाद पांडे और अन्य

20 सितम्बर 2004

[अरिजीत पसायत और सी.के. ठक्कर, जे.जे.]

सेवा कानून:

स्थानांतरण- केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत एक शिक्षक ने मध्य प्रदेश से जम्मू-कश्मीर राज्य से अपने स्थानांतरण को दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाते हुए चुनौती दी- ट्रिब्यूनल ने पाया कि आरोप स्थापित नहीं हुए- उच्च न्यायालय ने माना कि स्थानांतरण के आदेश में कोई अवैधता नहीं थी और ऐसा करने का कोई कारण नहीं था आवेदक की जगह लेने वाले शिक्षक को परेशान करें- हालाँकि, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य में पोस्टिंग दी जाए- उच्च न्यायालय का निर्देश टिकाऊ नहीं है और उसे खाली कर दिया गया है।

अंबानी कांता रे बनाम उड़ीसा राज्य, [1995] सप्ल। 4 एससीसी 169; भारत संघ बनाम एस.एल. अब्बास, एआईआर (1993) एससी 2444 और भारत संघ एवं अन्य। वी. जनार्दन देबनाथ और अन्य, [2004] 4 एससीसी 245, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2004 की सिविल अपील संख्या 6207

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.पी. 2003 की संख्या 3496 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 31.10.2003 से

राकेश के. खन्ना, सुश्री रश्मी खन्ना, शशांक शेखर और सूर्यकांत अपीलकर्ता की ओर से।

प्रतिवादियों की ओर से राज कुमार गुप्ता और सुश्री मृदुला रे भारद्वाज।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया:

अरिजीत पसायत, जे.:

अनुमति प्रदान की गई।

उभयपक्षों के विद्वान वकील को सुना।

प्रतिवादी क्रमांक 1, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, (एओसी) जबलपुर, म.प्र. में संस्कृत में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए। उनके स्थानांतरण एच से जम्मू-कश्मीर श्रीमती पर सवाल उठाया। वर्तमान अपील में प्रतिवादी क्रमांक 5 सुशीला पांडे थीं।

प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्थान पर जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') के समक्ष मूल आवेदन दायर किया। स्थानांतरण आदेश पर मुख्य रूप से कथित दुर्भावना के आधार पर हमला किया गया था और इसे सत्ता के दिखावटी प्रयोग में जारी किया गया दंडात्मक स्थानांतरण बताया गया था। ट्रिब्यूनल ने देखा कि दुर्भावना के आरोप स्थापित नहीं हुए और स्थानांतरण किसी भी तरह से दूषित नहीं हुआ। वर्तमान प्रतिवादी नंबर 1 की यह दलील कि उसे और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात किया जाना चाहिए, भी स्वीकार्य नहीं मानी गई। यह देखा गया कि ऐसी स्थिति जहां पति और पत्नी को एक साथ रखा जा सकता है वह हमेशा रिक्तियों की उपलब्धता और प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर निर्भर करेगी। यह नोट किया गया कि वर्तमान प्रतिवादी नंबर 1 और उसकी पत्नी ने एक विशेष स्थान पर लगभग 17 वर्षों तक एक साथ काम किया था। यह देखा गया कि प्रतिवादी नंबर 5 ने लगभग 15 वर्षों तक

जम्मू-कश्मीर में काम किया था और उसे एमपी में वापस आने के लिए पोस्टिंग दी जा रही थी, यानी, उसके मूल पोस्टिंग स्थान पर। मूल आवेदन खारिज कर दिया गया. बर्खास्तगी के आदेश को मप्र उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, बेंच जबलपुर ने कहा कि 5वें प्रतिवादी के स्थानांतरण में गड़बड़ी करने का कोई कारण नहीं है और यह भी माना कि जहां तक प्रतिवादी नंबर 1 का संबंध है, स्थानांतरण के आदेश में कोई अवैधता नहीं थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि वर्तमान प्रतिवादी नंबर 1 को एमपी राज्य में पोस्टिंग दी जाएगी। यह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का यह हिस्सा है जिस पर अपीलकर्ता केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हमला किया है। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। जहां तक उच्च न्यायालय के आदेश का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा 19.3.2004 को स्थगन का एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था।

स्थानांतरण जो कि सेवा की घटना है, इसमें न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना या दुर्भावनापूर्ण न हो या स्थानांतरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के किसी भी निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन न दिखाया जाए (अंबानी कांता रे बनाम राज्य सरकार देखें) उड़ीसा, [1995] सप्ल 4 एससीसी 169)। जब तक स्थानांतरण का आदेश दुर्भावना से नहीं किया जाता है या परिचालन दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाता है, तब तक न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। (भारत संघ बनाम एस.एल. अब्बास, एआईआर (1993) एससी 2444 देखें। किसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए और कहां तैनात किया जाना चाहिए, यह प्रशासनिक प्राधिकारी को तय करने का मामला है। जब तक कि स्थानांतरण का आदेश दुर्भावना से दूषित न हो या ऑपरेटिव के उल्लंघन में न किया गया हो किसी भी दिशानिर्देश या नियम में अदालतों को आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं

करना चाहिए। भारत संघ और अन्य बनाम जनार्दन देबनाथ और अन्य, [2004] 4 एससीसी 245 में यह इस प्रकार देखा गया था: एफ जी "कोई सरकारी कर्मचारी या जनता का कर्मचारी नहीं उपक्रम सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टें [2004] समर्थन। 4 एस.सी.आर. 580 को अपनी पसंद के किसी एक विशेष स्थान या स्थान पर हमेशा के लिए तैनात होने का कानूनी अधिकार है क्योंकि स्थानांतरणीय पदों के वर्ग या श्रेणी में नियुक्त किसी विशेष कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण न केवल एक घटना है, बल्कि सेवा की एक शर्त है। जनहित और लोक प्रशासन में दक्षता के लिए भी आवश्यक है। जब तक स्थानांतरण के आदेश को दुर्भावनापूर्ण अभ्यास का नतीजा नहीं दिखाया जाता है या ऐसे किसी भी स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जाता है, तब तक अदालतें या न्यायाधिकरण आम तौर पर ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वे थे संबंधित सेवा की प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के हित में पारित ऐसे आदेशों के विरुद्ध, अपीलीय प्राधिकारियों ने नियोक्ता/प्रबंधन के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय ले लिया है। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा उजागर किया गया था। लिमिटेड बनाम श्री भगवान, [2001] 8 एससीसी 574"। बी सी वर्तमान मामले में, ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट रूप से माना कि दुर्भावना शामिल नहीं थी और उच्च न्यायालय ने उस निष्कर्ष को परेशान नहीं किया। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय का आगे यह निर्देश कि प्रतिवादी क्रमांक 1 को म.प्र. में कहीं पदस्थ किया जाएगा, स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है। निर्देश को उचित ठहराने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

उच्च न्यायालय के आदेश का वह भाग निरस्त किया जाता है। उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

आर.पी.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी साधना सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।